हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 14 फ़रवरी 2026, समय 1810 (10 मिनट)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ सहित देश के चार शहरों में पी एम – ई बस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों रवाना किया।

पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी मे चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस अड्डे से 25 ई बसें रवाना की गई।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण की स्थापना को मंजूरी दी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है।

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर और चंडीगढ़ में पी एम – ई बस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इन 225 बसों में से 25 बसों को चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस अड्डे से हरी झंडी दिखाई गई, जहां पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा-

श्री मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मकसद शहरों में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना और सुगम परिवहन सेवा मुहैया करवाना है।

पी एम – ई बस सेवा योजना केंद्र सरकार की एक पहल है जिसे अगस्त 2023 में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के ज़रिए 169 शहरों में कुल 57,613 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए शुरू किया गया था। इसका मकसद ग्रीन अर्बन मोबिलिटी को बढ़ाना है और उन शहरों पर ध्यान देना है जहां व्यवस्थित बस सेवा की कमी है, और इसमें डिपो संरचना विकास भी शामिल है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा इसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढावा देने के लिए पूंजी जुटाना है।

मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह अनुदान-आधारित वित्तपोषण के स्थान पर बाजार-आधारित, सुधार-संचालित और परिणाम-उन्मुख अवसंरचना देश के शहरी विकास दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज ई टी नाउ वैश्विक व्यापार सम्मेलन को

संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने हर क्षेत्र में तरक्की की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद उद्योगों में निवेश को आकर्षित कर हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रगति की है।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई है, जिनका किसानों को प्रत्यक्ष रूप में लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

कृषि मंत्री यमुनानगर में बागवानी विभाग की ओर से खंड रादौर के त्रिवेणी गार्डन में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है। फलों व सब्जियों के बाजार मूल्य कम होने पर किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत प्रत्यक्ष रूप में मुआवजा उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि उत्पादकता एवं लागत में संतुलन बना रहें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बागवानी, मधुमक्खी पालन और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के प्रदर्शन हेतु उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना में भी हरियाणा देश में अग्रणी है।

एक भारत–श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम नगर निगम से पार्षदों व जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज फरीदाबाद पहुंचा।

फरीदाबाद की महापौर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी के कैंप कार्यालय में प्रतिनिधिमंडल का का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल तथा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर भी विशेष रूप से बैठक में

शामिल हुए। बैठक के दौरान नगर निगम फरीदाबाद द्वारा शहर के विकास के लिए अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। अधिकारियों ने ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली, स्वच्छता निगरानी व्यवस्था, सीसीटीवी आधारित निगरानी , ई-शासन सेवाएं तथा ऑनलाइन नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी साझा की। इसके अलावा वायु प्रदूषण कम करने के उपाय, हरित पट्टियों का विस्तार, पार्कों के सौंदर्यीकरण, वर्षा जल संचयन, सीवरेज प्रबंधन तथा सार्वजनिक सुविधाओं के उन्नयन पर भी चर्चा हुई।